उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 2, अंक : 18 ₹ 20/- 16-28 फरवरी, 2019

पोप फ्रांसिस का अरब दौरा

विश्व राजनीति में नया मोड़

और पढ़ें...

- महाराष्ट्र में दलित-मुस्लिम गठजोड़
- चीन में मुसलमानों पर धर्मांतरण के लिए दबाव
- सउदी अरब में महिलाओं की नौकरियों में वृद्धि
- केन्द्र सरकार द्वारा मुसलमानों को तोहफा

RNI No. DELHIN/2017/72722

Vol. 2, अंक 18
16-28 फरवरी, 2019

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह, आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाईट : www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक एवं प्रकाशक मनमोहन शर्मा द्वारा
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए
डी-51, प्रथम तल, हौज खास,
नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित
तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा. लि., ए 102/4,
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-II,
नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. महाराष्ट्र में दलित–मुस्लिम गठजोड़

II. आतंकवाद के खिलाफ भारत और सउदी अरब एकजुट

III. पॉपुलर फ्रंट की ओर से चुनाव की तैयारी

IV. उर्दू मीडिया की नजर में इमाम तौहिदी

V. साप्ताहिक नई दुनिया के निशाने पर गोवंश

VI. जमाते इस्लामी की ओर से मुसलमानों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की मांग

विश्व

I. अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति ट्रम्प को झटका

II. कनाडा में मस्जिद पर गोली चलाने वाले को 40 वर्ष की सजा

III. चीन में मुसलमानों पर धर्मांतरण के लिए दबाव

IV. जर्मन फौज में इमामों की भर्ती की मांग

V. आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान में समूचे परिवार की हत्या

VI. सउदी अरब और पाकिस्तान के बीच बीस अरब डॉलर का समझौता

VII. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार

VIII. ढाका में इज्तिमा

पश्चिमी एशिया

I. पोप फ्रांसिस का अरब दौरा : विश्व राजनीति में नया मोड़

II. ईरान में धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ

III. सउदी अरब में महिलाओं की नौकरियों में वृद्धि

IV. 40 हजार पाकिस्तानियों का निष्कासन

V. अरब जगत की पहली महिला गृह मंत्री

VI. ब्रिटेन में आईएसआईएस समर्थक महिला की नागरिकता खारिज

VII. पचास हजार कैदियों को माफी

VIII. सरकार विरोधियों को सजा

अन्य

I. शव दफन करने पर शिया सुन्नी विवाद

II. भारतीय हाजियों के कोटे में वृद्धि

III. केन्द्रीय वक्फ परिषद का पुनर्गठन

IV. जॉर्डन एयरवेज के खिलाफ प्रदर्शन

V. प्रो. बशीर अहमद फिर मुस्लिम लीग में

VI. केन्द्र सरकार द्वारा मुसलमानों को तोहफा

VII. तीन तलाक पर तीसरा अध्यादेश

सारांश

विश्व राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। ईसाई धर्म के दो हजार वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी पोप को किसी मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष ने सरकारी तौर पर दौरा करने की दावत दी है। वरना डेढ़ हजार वर्षों से ईसाईयों और मुसलमानों के बीच संघर्ष रहा है। दोनों में क्रुसेड युद्ध 200 वर्षों तक चला है। विश्व इतिहास में जो नया आश्चर्यजनक मोड़ आया है उसके पीछे किसकी भूमिका है, यह स्पष्ट नहीं है। मगर यह साफ है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पोप फ्रांसिस को अपने देश का दौरा करने की सरकारी तौर पर दावत दी है। राजधानी दोहा में पोप की प्रार्थना सभा का आयोजन करवाया गया और इस्लाम के इतिहास में पहली बार एक गिरजाघर के निर्माण करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने पोप को दोहा में एक भूखंड अर्पित किया। हैरानी की बात यह है कि भारतीय मीडिया ने इस घटना के महत्व को नजरअंदाज कर दिया।

चुनाव की धमक शुरू होते ही दलित मुस्लिम गठजोड़ के प्रयास तेज हो गए हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। यहां इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रकाश अम्बेडकर के संगठन वंचित बहुजन आघाडी से हाथ मिलाया है। इसके साथ ही अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी विभिन्न दलों से गठजोड़ करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विवादित पॉपुलर फ्रंट और जमाते इस्लामी भी इनमें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि जब से केन्द्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है उसे सत्ताविहीन करने के लिए दलित-मुस्लिम मोर्चा बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। हालांकि इसके साथ यह भी सच है कि इन प्रयासों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही हो गई थी मगर ये प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए।

आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत और सउदी अरब ने एकजुट होने की घोषणा की है। सउदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान का हाल का भारत का दौरा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2016 में नरेन्द्र मोदी ने सउदी अरब से मित्रता बढ़ाने के प्रयास शुरू किए थे और उन्होंने उस समय सउदी अरब का दौरा किया था। सउदी शासकों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा था। अभी तक सउदी अरब का झुकाव भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की ओर अधिक रहा है।

ईरान और पाकिस्तान के संबंध दिन-प्रतिदिन तनावपूर्ण हो रहे हैं। आर्थिक बदहाली का शिकार पाकिस्तान इस संकट से उबरने के लिए सउदी अरब के सामने भीख के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान ने यह आरोप लगाया है कि हाल में ही ईरान के ज़ाहेदान नगर के सैनिक छावनी में जो आत्मघाती हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ईरान ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने यह आत्मघाती हमला किया था वह पाकिस्तानी मूल का था।

मोदी सरकार की नजर में मुस्लिम महिलाओं का कल्याण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सरकार ने तीन तलाक पर कानूनी प्रतिबंध के बारे में तीसरी बार राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाया है। इससे पूर्व भी दो बार अध्यादेश जारी किए गए थे। इन अध्यादेशों को कानूनी रूप देने के लिए संसद में विधेयक भी पेश किए गए थे जो कि लोकसभा में तो पारित हो गए मगर राज्यसभा में विपक्षी दलों के असहयोग के कारण पारित नहीं हो पाए।

राष्ट्रीय

I

महाराष्ट्र में दलित-मुस्लिम गठजोड़

इत्तेमाद (19 फरवरी) के अनुसार डॉ. भीमराव अम्बेडकर के उत्तराधिकारी प्रकाश अम्बेडकर के संगठन वंचित बहुजन आघाडी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनावी समझौता कर लिया है। ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र के लोकसभा की सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी की लहर में शिवसेना और बीजेपी के गठजोड़ ने महाराष्ट्र में 52 प्रतिशत वोट प्राप्त करके 42 सीटें जीती थीं। जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 45 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे और इसने 6 सीटें जीती थीं। वंचित बहुजन आघाडी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर का कहना है कि जनता इन दोनों गठबंधनों के विकल्प की तलाश में है और उनका दल राज्य में तीसरे मोर्चे की भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हमारे साथ शामिल होते हैं तो हम भाजपा को सत्ता से वंचित कर देंगे। मगर अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भाजपा जीत जाएगी। गत दिनों अम्बेडकर के संगठन की ओर से महाराष्ट्र के कल्याण में एक जनसभा आयोजित की गई थी। इस जनसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाग लिया था और उन्होंने घोषणा की थी कि मुसलमान दलितों का साथ देंगे। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मजलिस ने वर्षों पूर्व इस बात को समझ लिया था कि दलितों और मुसलमानों की एकता बेहद जरूरी है इसलिए उसने हैदराबाद नगर निगम का महापौर और उप-महापौर दलितों को बनाया था। मजलिस की ओर से दलित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का सिलसिला जारी है। मजलिस आज भी अपने उसी प्रयास में जुटी हुई है। दलितों और मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और सत्ता में इन दोनों वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों का गठजोड़ होना बेहद जरूरी है। समाचारपत्र ने यह शिकायत की है कि दलित और मुसलमान दोनों ही उपेक्षा का शिकार रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया गया और उन्हें जेलों में डाला गया। अब समय आ गया है कि ये दोनों एकजुट हों और फासिस्ट ताकतों को पराजित करें।

इंकलाब (25 फरवरी) के अनुसार मुंबई में प्रकाश अम्बेडकर ने शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले शिवाजी पार्क में वंचित बहुजन आघाडी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दलित-मुस्लिम एकता से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही भयभीत हैं। वे यह समझती हैं कि अब महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सुषमा स्वराज को इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा आमंत्रित करने पर स्वयं को महिमामंडित कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि इस संगठन ने हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है और भारत पर उसपर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाता रहा है।

II

आतंकवाद के खिलाफ भारत और सउदी अरब एकजुट

इंकलाब (21 फरवरी) ने अपने मुख्य समाचार में कहा है कि सउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जारी किए गए संयुक्त विज्ञप्ति में आतंकवाद को भावी पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित करते हुए इस बात पर सहमति प्रकट की गई है कि मानवता के खिलाफ इस खतरे को प्रोत्साहन देने वाले देशों पर दबाव बनाया जाए। आतंकवाद को खत्म करने और आतंकवादियों का समर्थन करने वालों का खात्मा किया जाए। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने पूंजी निवेश, पर्यटन, आवास, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित पांच संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्तव्य में कहा है कि अपने रणनीतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गत सप्ताह पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों जैसे खतरों से विश्व को मुक्ति दिलाई जाए और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और उसके

उन्मूलन के लिए एक सुदृढ़ रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि हिंसक और आतंकवादी ताकतें हमारे युवकों को गुमराह न कर सकें। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सउदी अरब और भारत का इस सम्बन्ध में एक जैसा विचार है। सउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बयान में कहा है कि जहां तक आतंकवाद और अतिवाद का सम्बन्ध है यह हम दोनों देशों के लिए समान रूप से चिंता का विषय है। हम अपने दोस्त भारत को बताना चाहते हैं कि हम इस सिलसिले में उसे हर तरह का सहयोग देंगे। चाहे वह गुप्त जानकारी का आदान-प्रदान क्यों न हो। हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

समाचारपत्र के अनुसार दोनों देशों के नेताओं के इन बयानों से पकिस्तान पर यह दबाव डाला गया है कि वह आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। मोदी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पश्चिमी एशिया और खाड़ी देशों में 27 लाख भारतीय रहते हैं इसलिए इस क्षेत्र में शांति स्थापित रहना दोनों देशों के हित में है। समुद्री सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी में भी दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों के बीच सहयोग बढ़ेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दोनों का सहयोग महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

इंकलाब (20 फरवरी) के अनुसार प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हवाई अड्डे पर सउदी युवराज के स्वागत के लिए पहुंच गए। उनके साथ विदेश राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह भी थे। यह सउदी युवराज का पहला सरकारी दौरा है।

सउदी युवराज के दौरे पर टिप्पणी करते हुए **हमारा समाज** (22 फरवरी) ने कहा है कि सउदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भारत का साथ देने की घोषणा की है। यह भारत के लिए सफलता की बात है। इस घोषणा से शहीद फौजियों की विधवाओं का दु:ख कम होगा और नौजवानों को नया हौसला मिलेगा। भारत और सउदी अरब आतंकवाद के ठिकानों को खत्म करने के लिए आपस में गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। मोदी और सउदी युवराज का संयुक्त वक्तव्य काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आर्थिक सहयोग को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। जबकि सउदी युवराज ने कहा है कि सउदी अरब और भारत के सम्बन्ध अति प्राचीन हैं। यह रिश्ता हमारे खून में है। कई क्षेत्रों में हमारे हित संयुक्त हैं। सउदी अरब ने भारत में सौ अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने का जो फैसला किया है वह बेहद महत्वपूर्ण है।

समाचारपत्र ने कहा है, "जब आतंकवादी हमले में सेना के 40 नौजवान मारे गए थे और हमले के शक की सुई पाकिस्तान की ओर घूम रही थी तब सउदी युवराज का भारत दौरा सबसे ज्यादा रुचि का केन्द्र रहा। यह अलग बात है कि युवराज मोहम्मद ने इस हमले का पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं किया और खुद को इससे दूर रखा। मगर जब वे भारत आए तो उन्होंने आतंकवादी हमले की निंदा की। उन्होंने यह भी देखा कि पुलवामा के हमले के बाद भारत की जनता में कितना गुस्सा भरा हुआ है। हमें उम्मीद थी कि सउदी मेहमान भी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुटों का उल्लेख भारत आकर करेंगे। लेकिन सउदी युवराज ने भारत आकर आतंकवादी हमले की निंदा तो की मगर इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी न ठहराकर हमें निराश भी किया। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में पुलवामा हमलों पर पाकिस्तान को चेतावनी देते आ रहे हैं, इससे तो यही आशा थी कि वे सउदी अरब से भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने सख्त गुस्से को प्रकट करेंगे। हालांकि युवराज ने आतंकवाद को भारत और पाकिस्तान को खतरा बताया। मगर उन्होंने आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान की भावना को जरा भी आंच नहीं आने दी। एक बात यह साफ हो गई है कि सउदी अरब आतंकवाद के मामले में तो भारत के साथ खड़ा है लेकिन जहां बात पाकिस्तान की आएगी तो वह उससे दूरी बरकरार रखेगा।" सउदी अरब के विदेश मंत्री ने तो साफ शब्दों में कह दिया है, "उनका देश भारत और पाकिस्तान के विवादों में नहीं उलझेगा और न ही मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का विरोध करेगा।" इसलिए सउदी अरब का पाकिस्तान के बारे में इस दृष्टिकोण के सामने आने के बाद हमें यह देखना होगा कि आतंकवाद विरोधी अभियान और पाकिस्तान को दुनिया से अलग-थलग करने के प्रयास में हम कितने सफल रहे हैं।

सहाफत (22 फरवरी) ने सउदी युवराज के भारत दौरे का उल्लेख करते हुए अपने सम्पादकीय में कहा है कि सउदी अरब के युवराज के बारे में यह आम ख्याल है कि वे अपने देश के सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं और अधिकांश निर्णय स्वयं करते हैं। वे पाकिस्तान से होते हुए आए हैं इसलिए यह यकीन किया जाता है कि इमरान खान ने अपनी सरकार के दृष्टिकोण से उन्हें जरूर अवगत कराया होगा। इसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा और भारत में सौ अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत से हाजियों के कोटे में भी वृद्धि कर दी है और सउदी जेल में बंद 856 भारतीय कैदियों की रिहाई की भी घोषणा की है। दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है उसका एक लाभ तो यह हुआ है कि अगर भारत का कोई आतंकवादी सउदी अरब में होगा तो उसे भारत के हवाले कर दिया जाएगा।

इत्तेमाद (21 फरवरी) ने अपने सम्पादकीय में यह मत व्यक्त किया है कि युवराज सलमान एशियाई देशों की समस्याओं से स्वयं को अलग रखना चाहते हैं इसलिए उन्होंने भारत-पाकिस्तान दौरे के दौरान अफगानिस्तान का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के तनाव को कम करने के लिए भी कोई मशविरा नहीं दिया। इससे साफ है कि सउदी अरब को कश्मीर की समस्या से कुछ लेना-देना नहीं है। वह अन्य देशों की तरह ही इसे भारत-पाकिस्तान का आपसी मामला मानता है।

III

पॉपुलर फ्रंट की ओर से चुनाव की तैयारी

अखबार-ए-मशरिक (22 फरवरी) के अनुसार विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस लक्ष्य से 6 मार्च को दिल्ली में मुस्लिम राजनीतिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें चुनावी मैदान में उतरने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने अल्पसंख्यकों के लोक मांगों को पेश किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए देश भर से मुस्लिम चिंतकों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है जिनमें मुसलमानों की समस्याओं से सम्बन्धित एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा। साथ ही चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे मुसलमानों की मांगों को अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करें। केरल में पॉपुलर फ्रंट की कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि हालांकि 2019 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है मगर अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सभी राजनीतिक पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। जहां तक वर्तमान केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है उसकी नीतियां मुस्लिम विरोधी हैं जिसके कारण देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसक घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। भीड़ ने मुसलमानों को ही बीफ खाने या पशुओं के व्यापार करने के नाम पर कत्ल किया है। फ्रंट ने दावा किया कि एक सर्वेक्षण के अनुसार 2014 में भाजपा के शासन में आने के बाद उसके नेताओं द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयानों में 5 गुणा वृद्धि हुई है। ह्यूमन राइट्स वाच की एक रिपोर्ट के अनुसार भीड़ की हिंसा के अधिकांश मामलों में आरोपियों को कोई सजा नहीं मिली है। बाबरी मस्जिद के मामले में केन्द्र सरकार अवैध रूप से गिराई गई बाबरी मस्जिद के लिए न्याय प्राप्ति में बाधक बनी हुई है और वहां पर राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं। गैर-बीजेपी विपक्षी दलों के लिए बाबरी मस्जिद का मामला महत्वहीन बन गया है और उन्होंने मस्जिद के नवनिर्माण का जो वायदा किया था उसे पूरी तरह से भूला दिया है। आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण का कानून लाकर केन्द्र सरकार ने आरक्षण की संवैधानिक नींव को तबाह करने का प्रयास किया है और कांग्रेस एवं वामदलों ने इसका समर्थन किया है। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे काले कानून का दुरुपयोग मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों और विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जानबूझकर मुसलमानों को अपना निशाना बना रही है। बदलते हुए वर्तमान हालात में देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों और अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं से जानबूझकर स्वयं को दूर रख रही हैं। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए वह भी नरम हिंदुत्व का सहारा ले रही हैं। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि मुसलमान अपने भविष्य और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए गंभीरता से रणनीति तैयार करें और विपक्षी दलों को इस बात का अहसास दिलाएं कि मुसलमानों के वोट उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार ह्यूमन राइट्स वाच ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के शासनकाल में गोरक्षा के नाम पर मुसलमान अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बनाया गया है। इस संगठन की ओर से हिन्दुस्तान में गोरक्षा के नाम पर हिंसा के

शीर्षक से 104 पृष्ठों की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि मई 2015 से लेकर दिसम्बर 2018 के बीच 44 लोगों की हत्या भीड़ द्वारा की गई। इनमें से 36 मुसलमान थे। अधिकांश मामलों में पुलिस ने हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार को इन हमलों को उकसाने वालों या उन्हें उचित ठहराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट में चार राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के 11 केसों का जिक्र है जिनमें कुल 14 व्यक्ति मारे गए थे।

IV

उर्दू मीडिया की नजर में इमाम ताहिदी

शिया विद्वान इमाम मोहम्मद ताहिदी के भारत आगमन और उनके द्वारा कश्मीर के मामले पर भारत के पक्ष में दिए गए भाषणों का उर्दू समाचारपत्रों ने पूर्णत: बहिष्कार किया है। जबकि दूसरी ओर उनके खिलाफ उर्दू समाचारपत्रों ने जोरदार अभियान छेड़ दिया है।

साप्ताहिक नई दुनिया (18 फरवरी) ने एक समाचार प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है, 'हिन्दुस्तान के चुनाव अभियान में नया भगवा जोकर इमाम ताहिदी', दूसरा शीर्षक है, 'मुसलमानों के खिलाफ एक और तारीक फतह'। इस समाचार के साथ इमाम ताहिदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यन स्वामी का चित्र प्रकाशित किया गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि तैयार हो जाइये। हिन्दुस्तानी मुसलमानों में फूट पैदा करने के लिए एक और विदेशी मोहरा तैयार है। इस्लाम के खिलाफ विष उगलने और विभिन्न फिरकों के बीच मतभेद को हवा देने के लिए भगवा बिरादरी ने अब ईरान के भगौड़े मोहम्मद ताहिदी की सेवाएं प्राप्त की है जो कि खुद को 'इमाम अमन' कहता है और कई वर्षों से आस्ट्रेलिया में डेरा डाला हुआ है मगर वह 'रोजगार' के लिए भारत में कदम रख चुका है। उसके आगमन के साथ भारतीय मुसलमानों और विशेष तौर पर शियाओं में काफी बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि इससे पूर्व एक और 'बेहुदा' 'पाकिस्तानी भगौड़े' तारिक फतह को कैनेडियन नागरिक के तौर पर भारत में पलकों से लेकर गोद तक में बैठाया गया। जिसने हिन्दुस्तानी मुसलमानों की विचारधारा से लेकर उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठाई। अब सुना है कि वह इन दिनों कैंसर से युद्ध करने में व्यस्त है। इसलिए एक नया नमूना तैयार किया गया है। स्वयंभु इमाम ताहिदी वैसे तो एक सांस्कृतिक संगठन की दावत पर भारत आया है मगर उसकी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से खूब मुलाकातें हो रही हैं जिनमें जनाब सुब्रमण्यन स्वामी भी शामिल हैं। एक इस्लाम दुश्मन सिरफिरे को आम चुनाव से पूर्व इस तरह से निमंत्रण देना और फिर मीडिया में उसकी उधमबाजी इस बात का संकेत है कि असली खेल कुछ और है। एक यहूदी एजेंट जिसको ईरान से निकाल दिया गया था, अब अमेरिका और सउदी अरब के लिए काम कर रहा है। आजकल यहूदी और सउदी दोस्ती तेजी से बढ़ रही है। जो भारत पर भी मेहरबान है। इसलिए ताहिदी के आगमन के पीछे खेल की कड़ियां स्वत: जुड़ती जा रही हैं। एक समय 'इमाम मेहदी' होने का दावा करने वाला ताहिदी आस्ट्रेलिया से हिन्दुस्तान आया हुआ है क्योंकि उसे जी न्यूज ने दावत दी है। वह मुल्क में शिया-सुन्नियों के खिलाफ झूठी बातें बोलेगा। उसने आस्ट्रेलिया में ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी एमआई-6 की ओर से काम किया है। आस्ट्रेलिया में उसने सबसे पहला अपना सेंटर खोला जिसमें शराब को हलाल करार दिया और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को मीरादार कहने का सिलसिला शुरू किया। अब भारत में उसकी आवभगत को देखकर मुसलमान हैरान तो नहीं मगर परेशान जरूर हैं। क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों में मतभेद पैदा करना है। यही कारण है कि इसके खिलाफ मजलिस उलेमा-ए-हिन्द ने सख्त नाराजगी प्रकट की है। शिया नेता मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भी लिखा है जिसमें ताहिदी के भारत आगमन का विरोध किया गया है और सरकार से यह मांग की गई है कि उसके सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि इसका न तो इस्लाम से कोई संबंध है और न ही वह शिया सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। ऐसे व्यक्ति को भारत बुलाने का लक्ष्य है सिर्फ अशांति फैलाना।

तारिक फतह ने ट्वीटर पर लिखा है कि इमाम अमन के आगमन से हिन्दुस्तानी मौलवियों में घबराहट है। जिसके जवाब में मोहम्मद ताहिदी ने इसके ट्वीटर पर मजाक उड़ाया है और कहा है कि जो उसका विरोध कर रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ 'जवाद का कुत्ता' होता है। मोहम्मद ताहिदी का कहना है कि "मेरी नई पुस्तक 'ट्रेजेडी ऑफ इस्लाम' है जिसको मैंने 400 घंटे की रिसर्च के बाद लिखा है। अगर मेरी हत्या होती है तो इसका कारण यही पुस्तक होगी।" सोशल मीडिया पर उसका जबर्दस्त स्वागत हो रहा है और उसे भारत का मेहमान

बताया जा रहा है। एक ईरानी भगौड़ा 'नूर नजर' बन रहा है। इसके ट्वीटर पर लिखा है, "यहूदी हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मन इस्लामपरस्त हैं।" इस स्वयंभु इमाम ने ट्वीटर पर पांच बार पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था और कहा था कि "मैं पाकिस्तान का दौरा नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसे जायज देश नहीं मानता। वह धर्म के नाम पर ठगों का गिरोह चला रहा है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया जा रहा है। वह आतंकवादियों का स्वर्ग है। उसका इतिहास खूनी और काला है।" हैरानी की बात यह है कि वह अब हिन्दुस्तानी मुसलमानों में फूट के बीज बो रहा है।

सहाफत (7 फरवरी, 2019) के अनुसार इराकी मूल के ईरान में पैदा हुए और आस्ट्रेलिया में रह रहे इमाम मोहम्मद ताहिदी के भारत में आगमन से नया विवाद शुरू हो गया है। ताहिदी अपने आप को इमाम ऑफ पीस कहते हैं। वे दिल्ली के एक संगठन के बुलावे पर भारत आए हैं और वे दिल्ली में भाजपा के नेताओं से इस्लाम के बारे में बातचीत करेंगे।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि तौहिदी विवादित व्यक्ति हैं और वे इस्लाम के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इंटरनेट पर जो सामग्री मौजूद है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये इमाम पर अमन के नाम पर यहूदी एजेंडे पर काम कर रहे हैं ताकि यहूदी ताकतों को खूश करने के लिए इस्लाम को बदनाम किया जा सके। इमाम ताहिदी की पुस्तक 'द ट्रेजेडी ऑफ इस्लाम : एडमिशन ऑफ अ मुस्लिम इमाम' में कई बातें लिखी हुई हैं जिससे मुसलमानों और विशेष रूप से शियाओं में काफी नाराजगी है। किसी भी बहाने ईरान को भला-बुरा कहने वाले इमाम ताहिदी ने 2010 में अयातुल्लाह सादिक शिराजी से शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि लखनऊ के रहनेवाले मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि इस इमाम का शिराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दैनिक इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार मजलिस उलेमा ए हिन्द ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर जी टीवी द्वारा इमाम ताहिदी को बुलाने की निंदा की है और गृहमंत्रालय से मांग की है कि ताहिदी के सभी कार्यक्रमों पर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए। मजलिस उलेमा ए हिन्द के महामंत्री मौलाना कल्ब जवाद ने गृहमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि इस व्यक्ति का शिया सम्प्रदाय और इस्लाम से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उसके वीडियो, पुस्तकें और भाषण सभी इस्लाम विरोधी हैं और शिया विचारधारा के खिलाफ हैं। ऐसे व्यक्ति को भारत आने की अनुमति देने से देश में तनाव उत्पन्न होगा और किसी भी अप्रिय घटना के लिए भारत सरकार पूर्णत: दोषी होगी। इस पत्र पर अन्य कई शिया नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

V

साप्ताहिक नई दुनिया के निशाने पर गोवंश

साप्ताहिक नई दुनिया (18 फरवरी) के अनुसार जब गायें वोट दिलाने का जरिया बन जाएं तो सरकार इसका ख्याल क्यों न रखे? वह बीजेपी की हो या कांग्रेस की। इस राजनीति के निशाने पर पहले भी मुसलमान थे और अब भी मुसलमान हैं। मध्य प्रदेश के पुरानी बीजेपी सरकार के शासनकाल में मुसलमान निशाना बनते थे। लेकिन अब जबकि रियासत में सरकार बदल चुकी है और कांग्रेस सत्ता में है। हाल में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गोवध करने के आरोप में तीन मुस्लिम व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। हालांकि मध्य प्रदेश में गोवध कानूनन प्रतिबंधित है और इस जुर्म की सजा भी तय है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर सवाल उठना लाजिमी है। खुद कांग्रेस के अंदर से भी इस मामले पर आवाज उठ रही है और कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने भी इस मामले को उठाया है। दूसरी तरफ, राज्य की कमलनाथ सरकार गायों के संरक्षण और गोशालाओं के निर्माण के लिए जनता पर नया टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। साफ है कि सरकार की गोभक्ति का खामियाजा राज्य के गरीबों, किसानों और आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। यह गोभक्ति चुनाव के कारण कुछ और ही ज्यादा उमड़ कर सामने आ रही है। कांग्रेस सरकार बीजेपी की पुरानी सरकार से भी बढ़कर खुद को गोभक्त जाहिर करना चाहती है और नरम हिन्दुत्व की राह पर चलकर आम चुनाव जीतने का स्वपन देख रही है। ऐसा ही एक फैसला राज्य के तीर्थयात्रियों को मुफ्त कुंभ स्नान के लिए भेजने के बारे में भी है। हालांकि सरकार के पास पैसे नहीं है मगर चुनाव से पूर्व वह कुछ पैसे गायों पर भी खर्च करना चाहती है ताकि वह बीजेपी से बढ़कर खुद को हिन्दुवादी दिखा सके। सवाल यह है कि इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा? इसलिए कमलनाथ सरकार महंगी कारों पर गाय टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। अगर यह टैक्स लगाया जाता है तो गाय कल्याण के लिए टैक्स लगाने वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेसी सरकार पहली होगी। योगी सरकार पहले ही

नागरिकों पर गाय टैक्स लगाने का निर्णय कर चुकी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के मॉडल को भी देखा जा रहा है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने राज्य में एक हजार गोशालाओं को बनाने की योजना बनाई थी और एक कमेटी बना दी थी जो इस बात पर विचाार कर रही है कि गायों पर खर्च करने के लिए कहां-कहां से पैसा बटोरा जाए। सरकार ने पहले यह योजना बनाई थी कि मंदिरों की खाली पड़ी भूमि पर गोशाला बना दी जाए। मगर पुजारियों के विरोध को देखते हुए यह योजना खटाई में डाल दी गई। अब यह दावा किया जा रहा है कि मनरेगा की योजना के तहत गोशालाओं का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हिन्दुत्व कार्ड खेलने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को मुफ्त कुंभ स्नान करवाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों को तीर्थयात्रा पर भेजने का सिलसिला शुरू किया था। अब कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों से विशेष कुंभ एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। यह यात्रा पांच दिनों की होगी और यात्रियों को मुफ्त यात्रा के साथ-साथ खाने-पीने और चाय आदि की भी सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक ट्रेन में दस-दस सुरक्षाकर्मियों को भी नियुक्त किया जाएगा।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य लेख में यह दावा किया है कि गाय योगी के लिए मुसीबत बन गई हैं। योगी सरकार में न तो लोग ही सुरक्षित हैं और न ही गाय। योगी का गोप्रेम किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। गायों से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान पूरी-पूरी रात जागकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। नाराज किसान अवारा गायों को स्कूलों और अन्य सरकारी भवनों में बंद कर रहे हैं। भूख और सर्दी के कारण गायें मर रही हैं जिससे जनता में भारी नाराजगी है। योगी सरकार ने बजट में गायों के लिए 612 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। राज्य में अवारा गायों की संख्या सात लाख से भी अधिक बताई जाती है। अभी तक सिर्फ 2 लाख 77 हजार गायों के लिए ही गोशाला की व्यवस्था है। पांच लाख से अधिक गाय अवारा घूम रही हैं जो कि किसानों और जनता के लिए सिरदर्द बन गई हैं।

VI

जमाते इस्लामी की ओर से मुसलमानों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की मांग

दावत (10 फरवरी) के अनुसार जमाते इस्लामी से सम्बन्धित मुस्लिम छात्र संगठन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसआईओ) ने एक चुनावी घोषणापत्र जारी किया है जिसमें देश के सभी राजनीतिक दलों से मांग की गई है कि वे अपने-अपने घोषणापत्र में देश के मुसलमानों को दस प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करें। इस छात्र संगठन ने यह आरोप लगाया है कि केन्द्र और राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार को लागू करने में विफल रही हैं। इस संदर्भ में यह मांग की गई है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और राजीव गांधी फेलोशिप की धनराशि में वृद्धि की जाए। इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाले लोगों को नेट पास करने के शर्त से भी मुक्त किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैम्पस स्थापित किए जाएं। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अरबी और इस्लामिक स्टडी के विभाग स्थापित किए जाएं और सभी विश्वविद्यालयों में अरबी और इस्लामिक स्ट्डी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अनिवार्य किए जाएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया की अल्पसंख्यक पहचान के संरक्षण का आश्वासन दिया जाए। सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अल्पसंख्यकों को हिस्सा दिया जाए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अन्य पब्लिक सर्विस कमीशनों में अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित सदस्यों को अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाए।

समाचारपत्र ने कहा है कि धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्ग के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। उन युवकों के पुनर्वास के लिए विशेष धनराशि निर्धारित की जाए जिन्हें आतंकवाद के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को स्वच्छ तरीके से अपनाया जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 197 को खत्म किया जाए। चुनावी घोषणापत्र को जारी करते हुए एसआईओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाबीद शाफी ने कहा कि मुसलमानों को अपने वोट उसी पार्टी को देने चाहिए जो हमारे चुनावी घोषणापत्र को लागू करने का आश्वासन देती है। जिस पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणापत्र जारी किया गया उसमें लाबीद शाफी, सैयद अजहरूद्दीन, फिरदौस अहमद, रेमेश ए.के., जामिया मिलिया इस्लामिया, सफवी, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, अनीस, दिल्ली विश्वविद्यालय, अबुल कलाम, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि के छात्र नेता उपस्थित थे।

विश्व

I

अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति ट्रम्प को झटका

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी संसद के उच्च सदन ने अफगानिस्तान और सीरिया से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के फैसले का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अफगानिस्तान और सीरिया से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की घोषणा कर चुके हैं। उच्च सदन सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैककोनेल की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन 70 लोगों ने किया जबकि 26 लोगों ने इसका विरोध किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकवादी अब भी अमेरिका के लिए खतरा हैं। प्रस्ताव में चेतावनी दी गई कि सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के कारण ये उग्रवादी पुनः इक्ट्ठे हो सकते हैं जिससे वहां राजनीतिक स्थिरता पैदा होगी और इसमें रूस और ईरान हस्तक्षेप कर सकते हैं। ट्रम्प प्रशासन अफगानिस्तान से सात हजार अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा भी कर चुका है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव का डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सदस्यों ने समर्थन किया है। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। सदन में भाषण देते हुए रिपब्लिकन सांसद रैंड पॉल ने कहा कि इन देशों में अमेरिका की ओर से काफी रकम खर्च की गई है। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए और यह धनराशि देश के विकास पर खर्च होनी चाहिए।

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार मास्को सम्मेलन की अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें यह घोषणा की गई है कि अफगानिस्तान से सभी विदेशी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा और वहां की भूमि को किसी अन्य देश के विरूद्ध इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि मास्को में तालिबान और अमेरिकी सरकार के बीच वार्ता चल रही थी जिसके समाप्त होने के बाद यह घोषणापत्र जारी किया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि विदेशी शक्तियां अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अफगान महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण दिया जाएगा और सभी को अभिव्यक्ति की आजादी होगी। तालिबान ने दावा किया है कि यह वार्ता सफल रही है और अप्रैल तक अमेरिका अफगानिस्तान में से अपने 14 हजार सैनिकों में से 7 को वापस बुलवा लेगा। इस बैठक में हालांकि अफगान सरकार ने भाग नहीं लिया किन्तु पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अन्य कुछ नेता जरूर शामिल हुए।

इंकलाब (7 फरवरी) के अनुसार अफगान-तालिबान के नेता शेर अब्बास ने कहा है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर ताकत से कब्जा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इससे अफगानिस्तान में शांति नहीं होगी। युद्ध से शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर हम तबतक युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होंगे जबतक विदेशी ताकतें अफगानिस्तान से बाहर नहीं चली जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में शरई कानूनों को लागू करना चाहते हैं। महिलाओं को इस्लामी शरा के अनुसार सभी अधिकार दिए जाएंगे। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और स्कूल भी जा सकेंगी एवं नौकरी भी कर सकेंगी।

जमाते इस्लामी के मुखपत्र **दावत** (10 फरवरी) ने अपने मुख्यपृष्ठ पर मास्को में हुई समझौता वार्ता की चर्चा करते हुए कहा है कि इस वार्ता में अफगान सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था क्योंकि तालिबान इस सरकार को मान्यता नहीं देते। अफगान नेताओं का यह सम्मेलन रूसी सरकार की मेजबानी में हुआ। अब मास्को में तालिबान ने इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान का संविधान पुनः बनाया जाए और उसका आधार शरियत हो। तालिबान ने अफगानिस्तान में चल रहे गैर-इस्लामी गतिविधियों को सख्ती से खत्म किया है। मादक पदार्थों के व्यापार को उन्होंने सख्ती से रोका है जिससे अमेरिका बौखला गया है। अफगानिस्तान इस्लामिक जगत का ऐसा एकमात्र देश है जिसके पास समुद्री तट नहीं है। लेकिन यह देश खनिज पदार्थों के भंडारों से भरपूर है। कई तरह के गैसों के आपार भंडार हैं। ब्रिटेन ने 1839 में अफगान सरकार का तख्ता पलटकर अपनी किसी कठपुतली को वहां बैठाया था। इसके बाद अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का खेल शुरू हो गया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के विभिन्न कबीलों को आपस में लड़वाकर वहां हफीज उल्लाह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बना दी। इसके बाद वहां अपनी एक कठपुतली बबरक कारमल को राष्ट्रपति बना

दिया। यह अमेरिका को सहन नहीं हुआ। उसने अफगानिस्तान में गृहयुद्ध को भड़काया और विभिन्न कबीलों को अस्त्र-शस्त्र और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। उन्हें सउदी अरब और पाकिस्तान का समर्थन भी प्राप्त हो गया। भारत सरकार भी सोवियत यूनियन का समर्थन करती रही। मगर सोवियत यूनियन धीरे-धीरे कमजोर हो गया और अमेरिका ताकतवर होता गया। इसके बाद तालिबान एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभरे और अमेरिका से टक्कर लेने लगे। अमेरिका को एक दिन के लिए भी चैन नहीं मिला। आज भी वहां पर आधे से अधिक देश पर तालिबान का शासन है। तालिबान चाहते हैं कि अमेरिका अपनी फौज और अपना अस्त्र-शस्त्र दोनों वापस ले जाए।

II

कनाडा में मस्जिद पर गोली चलाने वाले को 40 वर्ष की सजा

इत्तेमाद (10 फरवरी) के अनुसार कनाडा की क्यूबेक नगर में एक मस्जिद पर गोली चलाने वाले एक व्यक्ति को 40 वर्ष कैद की सजा दी गई है। इस हमले में छह लोग मारे गए थे। यह हमला 29 वर्षीय कनाडा के नागरिक एलेक्जेंडर ने किया था। न्यायालय ने उसे फांसी की सजा देने की मांग को रद्द कर दिया। क्योंकि कनाडा में सजा-ए-मौत खत्म की जा चुकी है। जज ने कहा है कि यह हमला मुसलमानों के प्रति घोर नफरत का उदाहरण है और कनाडा के इतिहास में यह शर्मनाक घटना है। आरोपी को चार मुकदमों में 150 वर्ष कैद की सजा दी गई है। उसे 40 वर्ष तक जेल में रहने के बाद ही पेरोल पर रिहाई मिल सकती है। जज ने कहा कि इससे पहले इसे जमानत पर या पेरोल पर किसी भी सूरत में रिहा न किया जाए।

III

चीन में मुसलमानों पर धर्मांतरण के लिए दबाव

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (9 फरवरी) के अनुसार मानवाधिकारों के रक्षक 16 बड़े संगठनों ने यह मांग की है कि चीन में दस लाख मुसलमानों पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। समाचारपत्र ने मांग की है कि चीन द्वारा अल्गोर और अन्य मुसलमानों पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है इस उद्देश्य से उन्हें बड़े-बड़े कैम्पों में हिरासत में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ से यह मांग की गई है कि इन शिविरों के बारे में जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन गठित किया जाए। इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन संगठन के प्रवक्ता सारा ब्रुक्स ने कहा कि चीन ने अब यह स्वीकार किया है कि वह अल्गोर और अन्य तुर्की मूल के मुसलमानों को राजनीतिक और पेशेवर प्रशिक्षण देने के लिए शिविरों में रखता है। चीन ने यह भी दावा किया है कि यह कदम उसने आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए उठाया है। हालांकि चीन का यह दावा सरासर गलत है और चीन इन मुसलमानों की धार्मिक और नस्ली पहचान को मिटाना चाहता है ताकि वे चीन सरकार के समर्थक बने रहें।

उन्होंने कहा कि हमें इस बात का पता चला है कि इन शिविरों में बंद लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया जाता है और उन्हें अपनी आस्था बदलने के लिए प्रताड़ित किया जाता है और कई बार उनसे मारपीट भी की जाती है। हिरासत में लिए गए लोगों को अपने परिवारों से सम्पर्क रखने तक की अनुमति नहीं दी जाती। सिक्यिांग एक कैदखाना बन गया है जिसे लोगों पर एक विशेष संस्कृति को लादने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके बच्चों को रखने के लिए अलग अनाथालय खोले गए हैं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद चीन निष्पक्ष प्रयवेक्षकों को इन क्षेत्रों में जाकर जांच करने की अनुमति नहीं दे रहा है और विश्व के तमाम देश चुप्पी साधे हुए हैं। चीन के सिक्यिांग क्षेत्र में लगभग एक करोड़ अल्गोर मुसलमान रहते हैं जिनपर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

इत्तेमाद (11 फरवरी) के अनुसार तुर्की ने चीन से मांग की है कि वह अल्गोर मुसलमानों के नजरबंदी कैम्प फौरन बंद करे। तुर्की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हामी ऑक्सोय ने कहा है कि अब इस बात को सभी लोग जानते हैं कि चीन ने दस लाख से ज्यादा मुसलमानों

को नजरबंद कर रखा है। यह मानवाधिकारों का हनन है। हाल में ही अल्गोर के संगीतकार अब्दुल रहीम हयात की ऐसी ही एक कैम्प में मौत हो गई है जिसे एक गाने के कारण आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। वे ईरानी संगीत का साज बजाते थे और अल्गोर भाषा और मुसलमानों की अलग पहचान के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने नागरिक अधिकारों के लिए 2009 से चीन सरकार के खिलाफ संघर्षरत्त हैं। इससे पूर्व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप ईरदोगन ने चीन पर आरोप लगाया है कि चीन में मुसलमानों का वंशान्मुलन किया जा रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वह इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करे।

IV

जर्मन फौज में इमामों की भर्ती की मांग

दावत (10 फरवरी) के अनुसार जर्मनी में यह मांग की जा रही है कि वहां की सेना में भर्ती मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए इमामों को भर्ती किया जाए। जर्मनी में ईसाईयों के बाद मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जर्मन सेना में मुसलमानों की संख्या डेढ़ हजार के लगभग है। नरीमन रैंके जर्मन नौसेना की एक मुस्लिम महिला अधिकारी हैं जो कि 1969 में जर्मनी में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई थीं। उन्होंने कहा है कि ईसाई सैनिकों के लिए तो पादरियों की व्यवस्था है मगर मुसलमानों के लिए नहीं। इस्लामिक कांफ्रेंस नामक एक मुस्लिम संगठन ने आरोप लगाया है कि जर्मन सरकार जानबूझकर मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है।

V

आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान में समूचे परिवार की हत्या

इत्तेमाद (11 फरवरी) के अनुसार साहिवाल के समीप आतंकवाद विरोधी पुलिस के एक दस्ते ने एक परिवार के आठ सदस्यों को दिनदहाड़े गोली से उड़ा दिया। मारे जाने वाले लोगों में पुरूष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया था कि जिनलोगों को गोली से उड़ाया गया है उनके सम्बन्ध आतंकवादी संगठनों से थे। मगर इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में नागरिकों के द्वारा जो उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है और उसने इस घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों की हत्या की है उन्हें किसी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा। इस परिवार का केवल एक सदस्य आठ वर्षीय बच्चा ही जिंदा बचा है। जिसने कल जांच टीम के सामने अपना बयान देते हुए कहा कि वह अपने पिता खलील अहमद, मां, बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ लाहौर से एक कार में पेशावर जा रहे थे और इस कार को उनका एक पड़ोसी जिशान चला रहा था। साहिवाल के समीप पुलिस की दो जीपों में सवार नकाबपोश लोगों ने उनकी कार को घेर लिया और आते ही कार चालक को गोली से उड़ा दिया। बच्चे ने यह भी बताया कि इसके बाद उसके पिता ने इन पुलिस वालों को यह पेशकश की थी कि यदि उसके परिवार की जान बक्श दी जाए तो वे उन्हें कुछ हजार रूपया रिश्वत देने के लिए तैयार है। इसके बाद पुलिस के एक अधिकारी ने मोबाईल पर किसी व्यक्ति से बातचीत की। उसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसमें उसके माता–पिता और दोनों बहनें मारी गई। उसने कार के एक सीट के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई।

VI

सउदी अरब और पाकिस्तान के बीच बीस अरब डॉलर का समझौता

सियासत (18 फरवरी) के अनुसार सउदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंच गए। जैसे ही वे पाकिस्तानी की वायु सीमा में दाखिल हुए उन्हें पाकिस्तान वायुसेना के वायुयानों ने सुरक्षा प्रदान की। पाकिस्तान की भूमि पर कदम रखते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई और उनका स्वागत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया। इस अवसर पर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद

बाजवा भी मौजूद थे। उस दिन पाकिस्तान में आम अवकाश की घोषणा की गई। समाचारपत्र के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कार को स्वयं चलाकर युवराज को प्रधानमंत्री निवास ले गए। सउदी युवराज की सुरक्षा के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए थे।

दैनिक इंकलाब (19 फरवरी) के अनुसार दोनों देशों के बीच 20 अरब डॉलर की पूंजी निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सउदी अरब ग्वादर में एक बहुत बड़ा तेल शोधक कारखाना भी बना रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान के अनुरोध पर सउदी जेलों में बंद 2000 से अधिक पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि शेष कैदियों की रिहाई पर भी विचार किया जाएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने सउदी युवराज को पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड 'निशान पाकिस्तान' से नवाजा। युवराज के साथ जो 750 लोगों का काफिला आया हुआ था उनकी आवास के लिए इस्लामाबाद के सभी 5 स्टार होटल बुक थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सउदी युवराज ने स्वयं को सउदी अरब में पाकिस्तान का राजदूत कहकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। इमरान खान ने कहा है कि मैने युवराज से अनुरोध किया था कि वे सउदी अरब में काम करने वाले 25 लाख पाकिस्तानियों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि वे वहां के अरब निवासियों के साथ करते हैं। इस पर युवराज ने कहा कि आप सउदी अरब में मुझे अपना राजदूत समझें।

इत्तेमाद (19 फरवरी) के अनुसार सउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान विश्व के 20 बड़े देशों में शामिल हो जाएगा। इमरान खान ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सउदी अरब के व्यापार मंत्री माजिद बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार सम्बन्धों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। हम सभी चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि सउदी अरब पाकिस्तान में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करने को इच्छुक है।

VII

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार

सियासत (20 फरवरी) के अनुसार मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनपर गवाहों को रिश्वत देने का आरोप है। उनके खिलाफ 15 लाख डॉलर की संदिग्ध वसूली के मामले में मुकदमा चल रहा है। समाचारपत्र ने इस सम्बन्ध में अपने सम्पादकीय में कहा है कि मालदीव में यह परम्परा चल रही है कि सत्ता में आने वाला हर व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती को या तो गिरफ्तार कर लेता है या उसे देश से निष्कासित कर देता है। जब अब्दुल्लाह यामीन सत्तारूढ़ थे तो मोहम्मद नशीद को उन्होंने न केवल राष्ट्रपति के पद से बर्खाश्त कर दिया था बल्कि उन्हें देश से भी निष्कासित कर दिया है। अब मोहम्मद नशीद की पार्टी सत्ता में है तो वर्तमान सरकार ने अब्दुल्लाह यामीन को कैद कर दिया है। उनपर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुकदमें में गवाहों को रिश्वत देने का प्रयास किया। उनपर सत्ता से वंचित होने के बाद अवैध सूत्रों से डेढ़ मिलियन डॉलर वसूल करने का आरोप लगाया गया है। जब राजधानी माले में उन्हें पुलिस की निगरानी में जेल में ले जाया जा रहा था तो वहां पर पहले से ही कई विरोधी नेता कैद हैं। अब्दुल्लाह यामीन ने अपने शासनकाल में कई विरोधी नेताओं जेल में डाल दिया था और कई लोगों को मालदीव से निष्कासित कर दिया था। अब सत्ता परिवर्तन के बाद उनके विरोधी वापस लौट आए हैं। इनके विरूद्ध अब्दुल्लाह यामीन के शासनकाल में जो मुकदमें दर्ज किए गए थे अब सरकार ने वह वापस ले लिए हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि मालदीव कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और उसका आर्थिक ढांचा छिन्न-भिन्न हो चुका है। मोहम्मद नशीद ने यह आशा व्यक्त की है कि भारत जैसे मित्र देश आर्थिक संकट से उबरने के लिए उन्हें सहायता देंगे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन की सरकार का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था। उनके शासनकाल में चीन से जो कर्ज लिया गया था अब उसकी वापसी वर्तमान सरकार के लिए टेढ़ी खीर बन गई है। वर्तमान सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यामीन के शासनकाल में चीन से जो कर्ज प्राप्त किया था वह कितना था और उसे कहां-कहां खर्च किया गया था? नशीद ने आरोप लगाया है कि यामीन ने अपना देश चीन के पास गिरवी रख दिया था। मालदीव पर इस वक्त तीस बिलियन डॉलर का कर्ज है। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनसंख्या मात्र 5 लाख है और प्रति व्यक्ति

आय लगभग 15 हजार डॉलर है। इसलिए इतने बड़े कर्ज का भुगतान करना सरकार के लिए कठिन है। ज्ञातव्य है कि मालदीव मॉमून अब्दुल गय्यूम और मोहम्मद नशीद के शासनकाल में भारत के बहुत समीप रहा। लेकिन अब्दुल्ला यामीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और उन्होंने चीन से दोस्ती गांठ ली।

VIII

ढाका में इज्तिमा

अखबार-ए-मशरिक (20 फरवरी) के अनुसार ढाका में तब्लीगी जमात द्वारा एक इस्लामी इज्तिमा का आयोजन किया गया जिसमें 50 लाख लोगों के भाग लेने का दावा किया गया है। तब्लीगी जमात का बांग्लादेश में यह 54वां विश्व सम्मेलन है जिसमें तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी और उनके साथियों ने हिस्सा लिया। यह इज्तिमा पांच दिनों तक जारी रहा। इससे पूर्व इसी जगह पर तब्लीगी जमात के दूसरे गुट मौलाना जब्बार हुसैन की ओर से दो दिवसीय तब्लीगी इज्तिमा का आयोजन किया गया था। इस्लामी नेताओं के अनुसार हज के बाद विश्व में यह सबसे बड़ा मुसलमानों का संगठन होता है। बांग्लादेश में इज्तिमा का आयोजन करने का सिलसिला 1967 से जारी है। तब्लीगी जमात की नींव 1926 में मौलाना मोहम्मद इल्यास कांधलवी ने रखी थी। यह संगठन देवबंदी विचारधारा के फक्का हनीफी से सम्बन्धित है। तब्लीगी जमात की ओर से अनेक गुट चालीस दिन या चार महीने या फिर एक साल तक इस्लाम के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जाता है और वे मस्जिदों में अपना डेरा डालते हैं। ज्ञातव्य है कि भारत में पिछले साल तब्लीगी जमात ने 139 इज्तिमाओं का आयोजन किया था। इन इज्तिमाओं का लक्ष्य इस्लाम का प्रचार करना था।

पश्चिमी एशिया

I

पोप फ्रांसिस का अरब दौरा

विश्व राजनीति में नया मोड़

इंकलाब (6 फरवरी) के अनुसार अरब देशों का दौरा करने वाले ईसाई धर्म के पहले पोप फ्रांसिस ने यह अपील की है कि मध्य-पूर्व में युद्ध बंद करके शांति स्थापित की जानी चाहिए और वहां के सभी नागरिकों को चाहे उनका कोई भी धर्म हो समान अधिकार मिलने चाहिए। संवाद समिति एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार पोप ने इस्लामिक विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय जामिया अल-अजहर के प्रमुख शेख अहमद अल तईब से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सर्वधर्म सम्मलेन को सम्बोधित किया। उन्होंने धार्मिक गुरुओं से कहा कि युद्ध के शब्द को उन्हें नामंजूर करना चाहिए। यमन, सीरिया, ईराक और लीबिया में चल रहे युद्ध को खत्म करना जरूरी है। ज्ञातव्य है कि यमन में सउदी एलायंस की ओर से हव्वासी विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया गया था और उसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार वहां की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए शांति स्थापना पर जोर दिया है। इस अवसर पर शेख अल तईब ने अपने सम्बोधन में कहा कि धर्म में किसी भी तरह से हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पोप फ्रांसिस और शेख अहमद ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि अल अजहर और वेटिकन आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इस अवसर पर अबूधाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण किए जानेवाले पहले गिरजाघर से सम्बन्धित दस्तावेज पोप को तोहफे के तौर पर पेश किया। पोप ने कहा कि मुझे आशा है कि मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण बेघर हुए लोगों का पुनर्वास होगा और सभी लोगों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। अबूधाबी रवाना होने से पूर्व रोम में हजारों लोगों को सम्बोधित करते हुए पोप ने कहा कि भूखे-प्यासे और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हजारों लोगों और बच्चों की फरियाद खुदा के पास पहुंच रही है।

अखबार-ए-मशरिक (12 फरवरी) ने पाकिस्तान के विख्यात स्तम्भकार नफीस सिद्दीकी का लेख पोप के अरब दौरे के बारे में प्रकाशित किया है। लेखक ने इस लेख में कहा है कि इतिहास में पोप फ्रांसिस पहले पोप हैं जिन्होंने अरब देश का दौरा किया है। अरब में इस्लाम की स्थापना हुई है। पोप को इस दौरे की दावत संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायेद ने दी थी। अरब और इस्लाम के इतिहास में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के स्टेडियम में किसी पोप ने ईसाईयों की भीड़ को संबोधित किया। समाचारपत्र के अनुसार इस कार्यक्रम में डेढ़ लाख ईसाईयों ने हिस्सा लिया था। सिद्दीकी के अनुसार पोप का यह दौरा कई दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य का नया युग शुरू हो सकता है जो मानव कल्याण के लिए बेहद जरूरी होगा। शेख मोहम्मद बिन जायेद ने पोप फ्रांसिस को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे का दावत देकर गैर-मुस्लिम दुनिया को एक नया संदेश दिया है जो समय के साथ-साथ बढ़ता जाएगा। इस्लामी इतिहास में शेख बिन जायेद का यह कदम बहुत साहसपूर्ण है।

दूसरी ओर पोप फ्रांसिस ने भी अरब का दौरा करके अपने साहस का परिचय दिया है। हालांकि इस दौरे का दोनों धर्मों से जुड़े हुए कट्टरपंथियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात 2019 में सहिष्णुता और भ्रातृत्व के वर्ष के रूप में मना रही है। इसी सिलसिले में पोप को न सिर्फ वहां पर आने की दावत दी गई बल्कि विभिन्न धर्मों में सामंजस्य के लक्ष्य से एक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस दौरे में दुबई के शासक ने पोप को एक भूखंड उपहार में दिया है जिसपर चर्च का निर्माण किया जाएगा। इस्लामिक इतिहास में किसी अरब देश में बनाया जाने वाला यह एकमात्र चर्च होगा। पोप फ्रांसिस ने शेख को एक फ्रेम किया हुआ सिक्का पेश किया जिसमें सेंट फ्रांसिस और मिस्र के कमाल मलिक के बीच होने वाली भेंट को दिखाया गया है। दोनों धर्मों के प्रमुखों में यह भेंट 1219 ई. में हुई थी। इस दौरे की एक खास बात यह है कि पोप फ्रांसिस और इस्लामिक जगत के सबसे बड़े सुन्नी शिक्षा संस्थान जामिया अल अजहर के मुफ्ती आजम शेख अहमद अल तईब ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई है कि वेटिकन और जामिया अल अजहर दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। मुसलमानों और ईसाईयों के बीच सैंकड़ों वर्ष तक जो युद्ध चला उसके कारण इन धर्मों के अनुयायियों के बीच जो कटुता पैदा हुई थी उसे आजतक किसी ने कम करने का प्रयास नहीं

किया था। ईसाई जगत में हालांकि पुनर्जागरण का युग भी आया जिसके कारण पश्चिमी देश अतिवाद और संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकले।

लेख में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस विभिन्न धर्मों के समन्वय के भी सबसे बड़े प्रचारक हैं। कुछ लोग इसलिए उनकी आलोचना भी करते हैं। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात से वापसी के दौरान पत्रकारों ने उनसे कई चुभते हुए प्रश्न किए। एक पत्रकार ने उनपर आरोप लगाया कि उनका झुकाव इस्लाम की ओर हो रहा है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यह उत्तर दिया, "मुझपर आरोप लगाने वाले सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बाकी सब का मुझे कठपुतली बताते हैं।" अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने क्रुसेड युद्धों का उल्लेख किया तो पोप फ्रांसिस ने उसपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ट्रम्प दीवारें बनाते हैं, पुल नहीं। शायद उन्होंने इसी भावना के तहत संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायेद के बारे में भी यह कहा जाता है कि उनका दृष्टिकोण आम अरब नेताओं जैसा नहीं है। कहा जाता है कि दोहा में पोप का जो दौरा हुआ है उसके पीछे मोहम्मद बिन जायेद के अतिरिक्त मोहम्मद बिन सलमान की भी भूमिका है। अब यह समय की मांग है कि विभिन्न धर्मों के बीच तालमेल को बढ़ाया जाए ताकि मानवता शांति के मार्ग पर चले। मगर इससे पूर्व इस्लामिक जगत में जो आंतरिक रूप से आपस में युद्ध चल रहे हैं उनको रोकने की भी बेहद जरूरत है।

II

ईरान में धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (10 फरवरी) के अनुसार ईरान और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित सिस्तान नगर में हुए एक धमाके में ईरान के अर्द्धसैनिक संगठन के 27 कर्मचारी मारे गए और 13 घायल हुए। आतंकवादी संगठन जैश-अल-अदल ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने आरोप लगाया है कि इस धमाके की योजना पाकिस्तान में तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि ईरान आतंकवादियों से हर हालत में बदला लेगा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे कुछ पड़ोसियों ने गलत रास्ता चुना है। पासदारान-ए-इंकलाब नामक अर्द्धसैनिक संगठन के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और सउदी अरब को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान इस आतंकवादी हरकत के बारे में सबकुछ जानता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह ईरानी सेना पर हुए हमले के आरोपियों को सजा दे वर्ना वह खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ईरान की राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष अली लारीजानी ने कहा है कि इस हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी और पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेवार है। इस तरह की घटनाओं से ईरान और पाकिस्तान के सम्बन्ध प्रभावित हो सकते हैं।

दैनिक सियासत (20 फरवरी) के अनुसार जिस व्यक्ति ने आत्मघाती हमला किया है उसकी पहचान हाफिज मोहम्मद अली के रूप में हुई है जो एक पाकिस्तानी नागरिक है।

सहाफत (18 फरवरी) ने कहा है कि सिस्तान में हुए हमले के कारण पाकिस्तान और ईरान के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया है। ईरान के जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो ईरान विदेशों में रहनेवाले किराए के आतंकवादियों को खुद सजा देगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ईरान के दुश्मनों को शरण दे रहा है और हम इस बात को जानते हैं कि इन आतंकवादी तत्वों के पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां शरण दे रही हैं।

III

सउदी अरब में महिलाओं की नौकरियों में वृद्धि

दावत (22 फरवरी) के अनुसार सउदी अरब में सरकार की नई नीति के कारण एक ओर तो विदेशी मूल के लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं मगर दूसरी ओर वहां के स्थानीय नागरिकों को दी गई नौकरियों में वृद्धि हुई है। गत दो वर्षों में पुरूष और महिला दोनों की संख्या

नौकरियों में बढ़ी है। अरब न्यूज के अनुसार गत एक वर्ष में सउदी नागरिकों को दो लाख साठ हजार नौकरियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त देश में सेल और अन्य क्षेत्रों में भी जो नौकरियां सउदी नागरिकों को मिली हैं उनमें से 48 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं ने ली हैं। जिन दो लाख साठ हजार नागरिकों को रोजगार मिला है उनमें से 1 लाख 25 हजार महिलाएं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 के पहली तिमाही में 44 हजार लोगों को नौकरियां मिलीं। जबकि 2018 में इसी अवधि में नौकरी पाने वालों में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। सउदी गजट के अनुसार इस वक्त सउदी अरब में छह लाख महिलाएं नौकरी कर रही हैं। रोजगार मंत्रालय के सहायक महानिदेशक नवाल अब्दुल्लाह के अनुसार सउदी सरकार ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 344 अरब रियाल का पूंजी निवेश किया है। इसके अनुसार 499 नई योजनाओं का सृजन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार उन महिलाओं को भी नौकरियां दी जा रही हैं जिनकी चार से अधिक बच्चे हैं।

IV

40 हजार पाकिस्तानियों का निष्कासन

अखबार-ए-मशरिक (17 फरवरी) के अनुसार तुर्की सरकार ने देश में अवैध रूप से रहनेवाले 50 हजार पाकिस्तानियों को निष्कासित करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में तुर्की सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को विधिवत सूचना भी दे दी है। तुर्की की सरकार के अनुसार उनकी जेलों में 50 हजार से अधिक पाकिस्तानी कैदी हैं जो कि अवैध रूप से तुर्की में दाखिल हुए थे। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तुर्की सरकार ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को जेलों में रखना सम्भव नहीं है इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इन कैदियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस पत्र पर पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया अभी व्यक्त नहीं की है। गत सप्ताह तुर्की सरकार ने 50 पाकिस्तानियों को अपने देश से निष्कासित कर दिया था।

V

अरब जगत की पहली महिला गृह मंत्री

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार चर्चित नेता रया अल हसन को लेबनान का गृहमंत्री बनाया गया है। इससे पूर्व वह लेबनान की गुप्तचर एजेंसी की प्रमुख थीं। रया ने अमेरिकन विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री प्राप्त की हैं। वह लेबनान के शासक दल फ्यूचर मुवमेंट पार्टी की सदस्य हैं। इससे पूर्व 2009 में वह लेबनान की वित्त मंत्री भी बनाई गई थीं और दो वर्षों तक वह इस पद पर रहीं।

ज्ञातव्य है कि लेबनान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रशासन में बढ़ाने का काम निरंतर चल रहा है। गत वर्ष लेबनान में हुए संसदीय चुनाव में पहली बार संसद की 128 सीटों में से छह सीटों पर महिलाओं की जीत हुई थी।

VI

ब्रिटेन में आईएसआईएस समर्थक महिला की नागरिकता खारिज

इंकलाब (21 फरवरी) के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने आईएसआईएस से सम्बन्ध रखनेवाली महिला शमीमा बेगम को नागरिकता से वंचित कर दिया है। इस तरह का फैसला पहली बार ब्रिटिश सरकार ने किया है। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश गृहमंत्री साजिद जाविद ने यह घोषणा की है। समीमा बेगम की उम्र 19 वर्ष है। 2015 में अपने दो सहयोगियों सहित आईएसआईएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए ब्रिटेन से वह सीरिया चली गई थी। पूर्वी लंदन में रहने वाले शमीमा के परिवारजनों ने कहा है कि 19 वर्षीय बेटी के गर्भ में पल रहे बच्चे को इस बात का अधिकार है कि वह ब्रिटेन के शांतिपूर्ण वातावरण में परवरिश पाए। गृहमंत्री साजिद जाविद का कहना है कि अगर शमीमा वापस आती है तो उसे ब्रिटेन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शमीमा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उसे अतिवादी

आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों में भाग लेने पर कोई अफसोस नहीं है। मगर वह ब्रिटेन वापस जाना चाहती है। शमीमा बेगम सीरिया में एक शरणार्थी शिविर में रह रही है। उसने दावा किया है कि वह 9 महीने के गर्भ से है और बच्चा पैदा करने के लिए वापस ब्रिटेन जाना चाहती है। उसने यह भी कहा है कि इससे पूर्व भी उसके दो बच्चे थे जो कि दोनों मर गए। उसने कहा कि उसके साथ ब्रिटेन से जो तीन लड़कियां सीरिया आई थीं उनमें से एक बमबारी में मारी गई। जबकि तीसरी लापता है।

दैनिक सहाफत (21 फरवरी) के अनुसार शमीमा बेगम के वकील तसनीम अकौंजी के अनुसार उन्हें ब्रिटिश सरकार के इस फैसले से निराशा हुई है और वह उसे न्यायालय में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। शमीमा बेगम ने कहा है कि वह ब्रिटिश सरकार से क्षमा और सहायता चाहती है। उसने कहा कि उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। बीबीसी से भेंटवार्ता में शमीमा ने दावा किया है कि वह कभी भी इस्लामिक स्टेट की पोस्टर गर्ल नहीं बनना चाहती थीं। अब वह ब्रिटेन में खामोशी से अपने बच्चे को पालना चाहती हैं। 1981 के ब्रिटिश नागरिक कानून के अनुसार गृहमंत्री किसी भी व्यक्ति को जनहित में नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। शमीमा बेगम ने दावा किया है कि उसने अपने बहन के ब्रिटिश पासपोर्ट पर सीरिया तक यात्रा की थी। मगर वहां पर उससे यह पासपोर्ट वापस ले लिया गया। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि शमीमा की मां बांग्लादेशी थी इसलिए वहां के कानून के अनुसार शमीमा बेगम भी बांग्लादेशी हैं। जबकि शमीमा का कहना है कि उसके पास कभी भी बांग्लादेश का पासपोर्ट नहीं रहा और न ही वह वहां कभी गई हैं। जहां तक शमीमा बेगम के नवजात बच्चे का सम्बन्ध है क्योंकि उसे ब्रिटिश नागरिकता से वंचित किए जाने से पूर्व ही इस नवजात का जन्म हो गया था इसलिए यह बच्चा भी ब्रिटिश नागरिक ही समझा जाएगा। गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शमीमा बेगम की नागरिकता खत्म करने का फैसला उच्च स्तर पर काफी सोच समझ के बाद किया गया है।

हमारा समाज (21 फरवरी) के अनुसार ब्रिटिश समाचारपत्र टाइम्स के एक संवाददाता ने शमीमा बेगम को एक शरणार्थी शिविर में ढूंढ निकाला था। एक सप्ताह पूर्व उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। शमीमा ने कहा कि पहले वह अपने बेटे को इस्लामिक स्टेट का लडाकू बनाना चाहती थी मगर वह अब उसे ब्रिटिश नागरिक बनाना चाहती है और उसे साथ लेकर ब्रिटेन वापस जाना चाहती है। ब्रिटिश गृहमंत्री साजिद जाविद ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में 100 से अधिक ब्रिटिश नागरिकों को पहले ही नागरिकता से वंचित किया जा चुका है।

VII
पचास हजार कैदियों को माफी

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 फरवरी) के अनुसार ईरान सरकार ने जेलों में बंद पचास हजार कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है। ईरानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सादिक लारिजानी ने कहा कि इस फैसले की पुष्टि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने कर दी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान में क्योंकि कोई राजनीतिक बंदी नहीं है इसलिए विरोधियों का यह प्रचार गलत है कि यह फैसला विश्व के दबाव के कारण उठाया गया है।

VIII
सरकार विरोधियों को सजा

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार बहरीन की सरकार ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण 18 नागरिकों को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही उनकी नागरिकता को भी रद्द कर दिया गया है। इन पर आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया गया है। बहरीन में इस्लाम जम्हूरियत नामक संगठन के प्रमुख जवाद फिरोज ने कहा कि गत छह वर्षों में अल खलीफा की सरकार 815 नागरिकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर चुकी है। अनेक लोगों को फांसी की सजा दी जा चुकी है और बहरीन सरकार विरोधियों को दबाने का काम कर रही है। ज्ञातव्य है कि बहरीन में सुन्नी और शियाओं के बीच काफी दिनों से संघर्ष चल रहा है।

अन्य

I

शव दफन करने पर शिया सुन्नी विवाद

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक कब्रिस्तान में शव को दफनाने पर शियाओं और सुन्नियों में जबर्दस्त विवाद उत्पन्न हो गया। बताया जाता है कि एक शिया व्यक्ति का निधन हो गया था और उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही थी। जब यह सूचना सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों को मिली तो वे मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हम अपने कब्रिस्तान में किसी शिया को दफन नहीं करने देंगे। विवाद को देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया मगर समझौता न हो सका। क्योंकि दोनों सम्प्रदाय कब्रिस्तान पर अपना अपना दावा बता रहे थे। पुलिस की निगरानी में कब्र खोदी गई और शव को दफना दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस बात का फैसला बाद में किया जाएगा कि यह कब्रिस्तान किसका है?

II

भारतीय हाजियों के कोटे में वृद्धि

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (21 फरवरी) के अनुसार भारत सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सउदी सरकार ने 2019 में हज के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों के कोटे में 25 हजार की वृद्धि की है। इससे पूर्व पौने दो लाख हाजियों का कोटा था। समाचारपत्र के अनुसार मुख्तार अब्बास नकवी ने सउदी युवराज से अनुरोध किया था कि वे हिन्दुस्तान में मुसलमानों की भारी जनसंख्या को देखते हुए हज के कोटे में वृद्धि करें।

III

केन्द्रीय वक्फ परिषद का पुनर्गठन

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 फरवरी) के अनुसार भारत सरकार ने केन्द्रीय वक्फ काउंसिल का पुनर्गठन किया है। इस काउंसिल में हालांकि बीस सदस्य होते हैं मगर अभी मोदी सरकार ने केवल दस लोगों का मनोनयन किया है। इसके अध्यक्ष केन्द्रीय अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री होते हैं और इसकी अवधि तीन वर्ष की होती है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार जिनलोगों को मनोनीत किया गया है उनमें रईस खान पठान (दिल्ली), हनीफ अली (हैदराबाद), मोहम्मद हारून (दिल्ली), डॉ. दरखशान अंदराबी (जम्मू-कश्मीर), वसीम राहत अली खान (मुंबई), डॉ. सैयद तनवीर नसरीन (कोलकाता), एस मुनव्वरी बेगम (तमिलनाडु), नौशाद टी.ओ. (केरल) और सैयद जीन अबुल दीन अली खान (राजस्थान) शामिल हैं।

ज्ञातव्य है कि पिछली वक्फ काउंसिल की अवधि हालांकि पिछले वर्ष 31 नवम्बर को ही समाप्त हो गई थी मगर नई काउंसिल का गठन नहीं किया गया था। इस काउंसिल में दिल्ली के दो सदस्य मनोनीत किए गए हैं जबकि तीन महिलाओं को भी मनोनीत किया गया है। दिल्ली से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कारी मोहम्मद हारून को भी जगह दी गई है। क्योंकि अगले महीने से आचार संहिता लागू हो जाएगी इसलिए सरकार ने इस काउंसिल का गठन किया है।

IV

जॉर्डन एयरवेज के खिलाफ प्रदर्शन

सहाफत (6 फरवरी) के अनुसार जॉर्डन एयरलाइंस ने ईरान की यात्रा के लिए सात-सात हजार रुपये में हवाई यात्रा के लिए टिकट देने का प्रस्ताव दिया था। अब उसने अपनी वेबसाइट में तकनीकी खराबी का हवाला देकर दिल्ली और तेहरान के बीच बुक किए गए तमाम टिकट रद्द कर दिए हैं। एयरलाइंस का कहना है कि हमने इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया था। जो लोग ईरान जाना चाहें उन्हें 35-35 हजार रुपये का टिकट खरीदना होगा। जिनलोगों ने सात-सात हजार रूपये का भुगतान किया है वे अपना धन वापस ले जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हजारों शियाओं ने सात-सात हजार के टिकट बुक करवाए थे। शिया उलेमा मौलाना जलाल हैदर नकवी ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

V

प्रो. बशीर अहमद फिर मुस्लिम लीग में

सहाफत (7 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम नेता प्रो. बशीर अहमद पुनः इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल कादिर, संगठन मंत्री ई.टी. मोहम्मद बशीर और राज्य सभा के सदस्य पी.बी. अब्दुल वहाब आदि लीगी नेताओं ने किया। ज्ञातव्य है कि प्रो. बशीर अहमद को उत्तर भारत में मुस्लिम लीग की जड़ें जमाने की जिम्मेवारी 1969 में मुस्लिम लीग के तात्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने सौंपी थी। मगर इसके बाद वे राजनीति से अलग हो गए थे। प्रो. बशीर ने कहा कि मुसलमानों की बदहाली को देखते हुए उन्होंने पुनः राजनीति में भाग लेने का फैसला किया है।

VI

केन्द्र सरकार द्वारा मुसलमानों को तोहफा

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। अजमेर दरगाह की प्रबंध समिति के प्रमुख अमीन पठान ने बताया कि यह विश्वविद्यालय 80 बीघा जमीन पर बनाई जाएगी और इसका सारा खर्च केन्द्र सरकार देगी। इसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाया जाएगा और इसकी आधी सीटें मुसलमान छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी। इस विश्वविद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य, कला के साथ-साथ इंजिनियरिंग और मेडिकल की भी व्यवस्था की जाएगी। इस विश्वविद्यालय में ख्वाजा गरीब नवाज और अन्य सूफियों की शिक्षा पर आधारित अनुसंधान करने के लिए एक विशेष चेयर की भी स्थापना की जाएगी। ज्ञातव्य है कि ख्वाजा का उर्स तीन मार्च को होने वाला है। इससे पूर्व ही इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने की योजना है।

VII

तीन तलाक पर तीसरा अध्यादेश

सहाफत (22 फरवरी) के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक पर प्रतिबंध के बारे में एक अध्यादेश जारी किया है। यह अध्यादेश तीसरी बार लाया गया है। इस अध्यादेश के तहत तीन तलाक को गैरकानूनी ठहराया गया है और तीन तलाक देने वाले को तीन वर्ष की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस संदर्भ में एक बिल लोकसभा में पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा में यह पारित न हो सका। इसलिए सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा। शीतकाली सत्र में लोकसभा में सरकार ने इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ जारी किया और उसे मंजूर भी करवा लिया। मगर राज्यसभा में यह फिर लटक गया। राज्यसभा में सरकार ने इसे पुनः पेश नहीं किया। क्योंकि लोकसभा भंग हो गई है इसलिए पुराना अध्यादेश स्वतः रद्द हो गया है। यही कारण है कि तीसरी बार सरकार को पुनः यह अध्यादेश लाना पड़ा है। इससे पूर्व केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीसरा अध्यादेश जारी करने का निर्णय किया था।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

Latest Publications

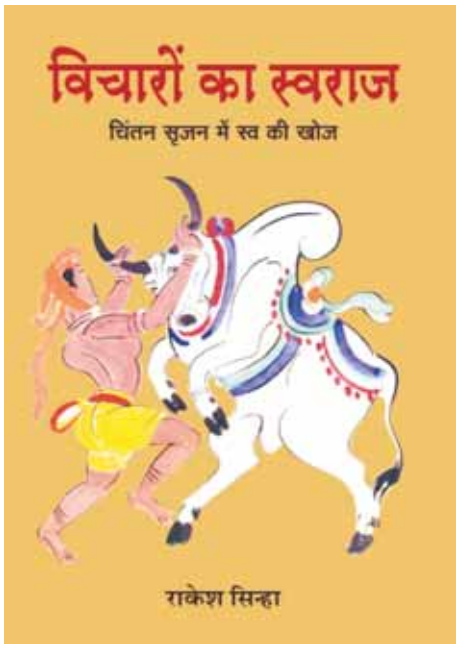

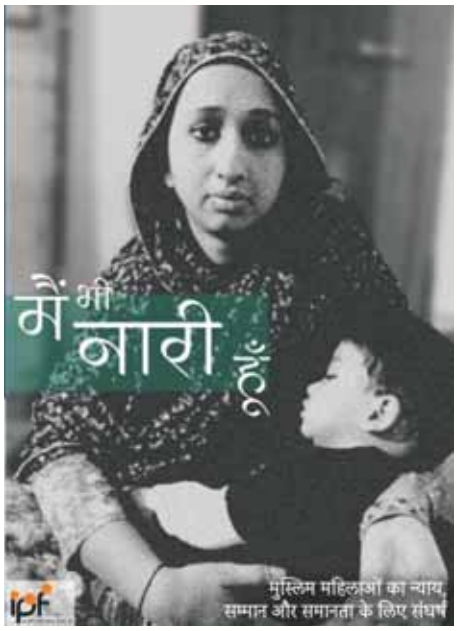

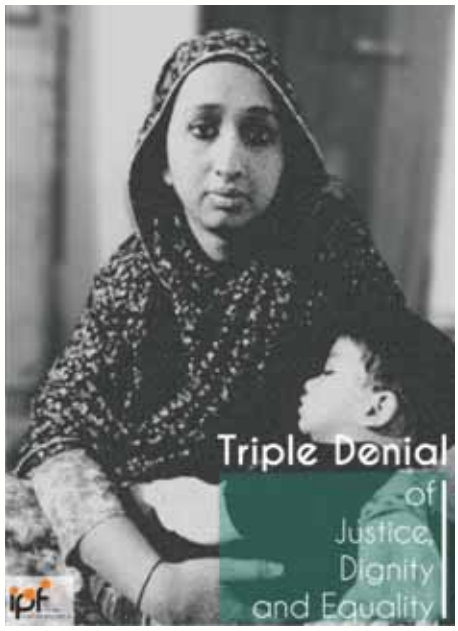

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org